



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 ज्येष्ठ 1937 (श0)
(सं0 पटना 612) पटना, बृहस्पतिवार, 4 जून 2015

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

28 मई 2015

एस0ओ0 116, दिनांक 4 जून 2015—‘बिहार जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) अधिनियम 2002’ (अधिनियम 18, वर्ष 2002) की धारा-7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्य सरकार, एतद् द्वारा, पटना उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य के सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में स्थित जिला व्यवहार न्यायालय में पदस्थापित एवं कार्यरत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-सहायक सत्र न्यायाधीश [सिविल जज (वरीय कोटि)] के न्यायालय को ‘बिहार जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) अधिनियम, 2002’ के अधीन दायरवादों के त्वरित विचारण हेतु अभिहित न्यायालय के रूप में गठित करती है;

- (क) इन न्यायालयों की स्थानीय अधिकारिता संबंधित प्रमंडल के सभी जिलों की राजस्व सीमाएँ होंगी;
- (ख) जहाँ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-सहायक सत्र न्यायाधीश पदस्थापित एवं कार्यरत न हों, वहाँ पदस्थापित एवं कार्यरत अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-सहायक सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, उक्त अधिनियम के अधीन दायरवादों के त्वरित विचारण हेतु, अभिहित न्यायालय होगा;
- (ग) यह अधिसूचना तुरंत प्रवृत्त होगी।

(सं0सं0 ए0/एक्ट-7/2003/3437/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अखिलेश कुमार जैन,

सरकार के सचिव।

28 मई 2015

एस0ओ0 117, एस0ओ0 116, दिनांक 4 जून 2015 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड(3) के अधीन उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0 ए0/एक्ट-7/2003/3437/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अखिलेश कुमार जैन,

सरकार के सचिव।

The 28th May 2015

S.O. 116, dated the 4th June 2015—In exercise of the powers conferred by Section 7 of 'The Bihar Protection of Interest of Depositors (In Financial establishments) Act 2002' (Act 18, 2002), the State Government of Bihar, in consultation with the High Court of Judicature at Patna, is hereby pleased to constitute the court of Chief Judicial Magistrate-cum-Assistant Sessions Judge [Civil Judge (Senior Division)] posted and working in the District Civil Courts situated in all the Divisional Headquarters of the State, as the designated court for the speedy trial of the cases filed under 'The Bihar Protection of Interest of Depositors (In Financial establishments) Act, 2002';

- (a) the Local jurisdiction of these Courts shall be the revenue limits of all the Districts of the concerned Division;
- (b) where the Chief Judicial Magistrate-cum-Assistant Sessions Judge is not posted and working, the court of Additional Chief Judicial Magistrate-cum-Assistant Sessions Judge shall be the designated court for the speedy trial of the cases filed under the said Act;
- (c) this notification shall come into force at once.

(F.No. A/Act-7/2003/3437/J.)

By order of the Governor of Bihar,

AKHILESH KUMAR JAIN,*Secretary to the Government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 612-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>